

स्वराज्य पार्थी

- ⇒ असहयोग आन्दोलन को रोकने के तत्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताश की भावना फैल गई।
- ⇒ और कांग्रेसी नेताओं में मतभेद उत्पन्न आया।

(स्वराज्यवादी/परिवर्तनवादी)

विधानमण्डलों का बहिष्कार कर उसमें भाग लेना चाहिए

Ex- चितरंजन दास

मोतीलाल नेहरू

मदनमोहन मालवीय, किटलभाई पटेल

जयकर।

(अपरिवर्तनवादी)

विधानमंडल में प्रवेश का अब भी विरोध किए वल्लभभाई पटेल, अंसारी, राजेन्द्र प्रसाद

- ⇒ परिवर्तनवादी का कहना था कि विधानमंडल में प्रवेश कर सरकारी कार्यों में बाधा डालेंगे, सरकार की कमजोरी को उजागर करेंगे और वहाँ से राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाएंगे जो उन उत्साह जगाने में उसका उपयोग करेंगे।

- ⇒ अपरिवर्तनवादी का कहना था कि अगर हम विधानमंडल में प्रवेश करते हैं तो जनता के बीच काम की अपेक्षा होगी जिससे राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ जायेगी और आपस में मतभेद बढ़ जायेगा इसलिए ये लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिन्दू-मुस्लिम एकता छुआ छूत उन्मूलन और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया।

उनका मानना था कि इससे धीरे-धीरे जनता संघर्ष के लिए एक बार पुनः तैयार होगा।

1922 का गया अधिवेशन

- = Dec 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ जिसमें अध्यक्ष → चितरंजन दास को बनाया गया।

- ⇒ इस अधिवेशन में चितरंजन दास तथा उसका सहयोगियों ने

विधान परिषद में प्रवेश पाने के लिए प्रस्ताव लाया लेकिन अपरिवर्तनवादियों ने उसका विरोध किया जिससे वह प्रस्ताव पास न हो सका। अतः मोतीलाल नेहरू तथा चितरंजन दास एवं उसके सहयोगियों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया।

1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्यपार्टी की स्थापना किये।

महयत्न → चितरंजन दास

सचिव → मोतीलाल नेहरू

⇒ स्वराज्यवादियों ने 1923 के होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया।

ध्यान दे :- स्वराज और अपरिवर्तनवादी भले ही अपने-अपने ढंग से काम कर रहे थे लेकिन उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों गुट भासनी से एकजुट हो गए।

⇒ Dec 1923 में दोनों पक्षों के महयत्न एक समझौता हुआ। स्वराजियों को कांग्रेस का एक अंग स्वीकार किया गया। स्वराजियों ने भी केवल एक शर्त छोड़कर (विधान परिषदों में भाग न लेने की वजह) बाकी ~~सभी शर्तें~~ कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया गया।

⇒ Nov-1923 में चुनाव होने वाला था स्वराजवादियों ने इस चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।

स्वराजियों का 'चुनाव घोषणा पत्र' :- १९२३

* चुनाव घोषणा पत्र में स्वराजियों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया।

प्रमुख बातें :- * भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य,

उल्लेख - के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है।

* अंग्रेजों की वास्तविक मंशा भारत के असिमित संसाधनों का अन्यायपूर्ण दोहन तथा भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना।

* स्वराजी, स्वशासन की राष्ट्रवादियों की मांग को परिषदों में उठाएंगे।

* अगर सरकार ने उनके मांगों की नामंजूर कर दिए, तो वे संयुक्त प्रयासों द्वारा परिषदों की कार्य को संचालित करने में अवरोध पैदा करेंगे।

Nov-1923 का चुनाव और स्वराजियों की सफलता

Nov 1923 में चुनाव सम्पन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली।

केन्द्रीय विधान परिषद में 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वायत्ततावादी

महयमान्त में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला

बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरा

तथा U.P तथा बम्बई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली

=> केन्द्रीय विधान परिषद में 24 सीट पर कब्जा उडिपैड्डेदल (जिन्ना का) का था।

=> स्वराजियों ने जिन्ना के पार्टी, तथा मदनमोहन मालवीय के पार्टी

साथ मिलकर केन्द्रीय विधान परिषद में संयुक्त मोर्चा बना लिया ।

- ⇒ कुछ समय बाद ~~आंतकवाद~~ आंतकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकारों तथा ~~स्वराजियों~~ स्वराजियों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया ।
- ⇒ ~~स्वराजियों~~ 1924 के आते-आते स्वराजियों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी ।
- ⇒ उसी बीच (1924) गाँधी जी स्वराजियों को साथ देने का निश्चय किया ।
- ⇒ 16 June 1925 को C.R. दास की मृत्यु से उन्हें और गहरा झटका लगा ।
- ⇒ लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय तथा ए.ए. कैलकर ने सरकार के साथ समर्पण तथा हिन्दू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की । और मोतीलाल नेहरू जैसे अ-प्रतिक्रियावादियों पर आरोप लगाया कि वे मांशाहारी तथा हिन्दू हितों के विरोधी हैं ठहकर स्वराज परी छोड़ दी ।

⇒ Note:- साइमन आयोग ने सन् 1922-1927 के बीच 112 आंतकवादी घटना घटने का उल्लेख किया ।

⇒ अंततः 1930 में सक्रिय अक्ता आन्दोलन छोड़ जाने के कारण ~~स्वराजवादियों~~ स्वराजवादियों ने विधान मंडल का दमन छोड़ दिया ।

स्वराजियों की उपलब्धि

* ये कजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे परिणामस्वरूप वायसराय को अपने विशेषाधिकार इसे पारित करना पड़ा था इस तरह इन्होंने नए विधानमण्डलों का असली चरित्र उजागर किया गया।

* स्वराजवादियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया।

* इनकी मांगों के परिणामस्वरूप 1924 ई० में सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए गुडरीमैन कमेटी

का गठन किया गया।

* 1924 में स्वराजियों के प्रयास के कारण सरकार ने राय को उद्योग को संरक्षण दिया

* 1925 ई० में विट्टलभाई पटेल को केन्द्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया।

* 1925 में मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर लिया

सेना की भर्ती करने के लिए

* 1928 में सरकार ने Public Safety Bill (PSB) को लाया लेकिन उसके विरोध में मत देकर उसे असफल कर दिया। स्वराजवादियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस विधेयक को भारतीय मुलामी विधेयक नम्बर 8 की संज्ञा दी

गाँधी-दास पैकट 1924 ई.

5 Feb 1924 को गाँधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया

Nov. 1924 में गाँधी जी और चितरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ जिसे गाँधी-दास पैकट कहते हैं उस

समझौते में हुई बातों को कांग्रेस के वेलगोप अधिनियम 1924 में स्वीकार कर लिया गया

⇒ इस समझौते में कहा गया की असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम न रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ की असहयोग की बात बिल्कुल बंद कर दी गई ताकि हिन्दुस्तान की स्वार्थों की रक्षा और दमन के नीति के विरुद्ध विभिन्न गुरु और पार्टियों मिलकर काम कर सकें।

⇒ स्वराज पार्टी को अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अभिन्न भेग के रूप में काम करें।

⇒ गाँधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन को संगठित करने और सम्पूर्ण देश में चरखा का प्रचार करने का कार्य दिया गया।

पतन के कारण

① देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु

② सरकार को सहयोग की नीति का अंश - प्रारम्भ में सरकार को असहयोग किया परन्तु बाद में सरकार को सहयोग करने लगा।

③ 1926 के निर्वाचन में प्रत्याशित सफलता न मिलना

④ स्वराज्य दल में मतभेद

⑤ वे विधान मंडलों की शक्तियों से विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहा।

⑥ पार्टी में छुसपैट कर रहे सम्प्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहा।

साइमन कमीशन 1928

↳ भारतीय संवैधिक आयोग

पृष्ठभूमि :

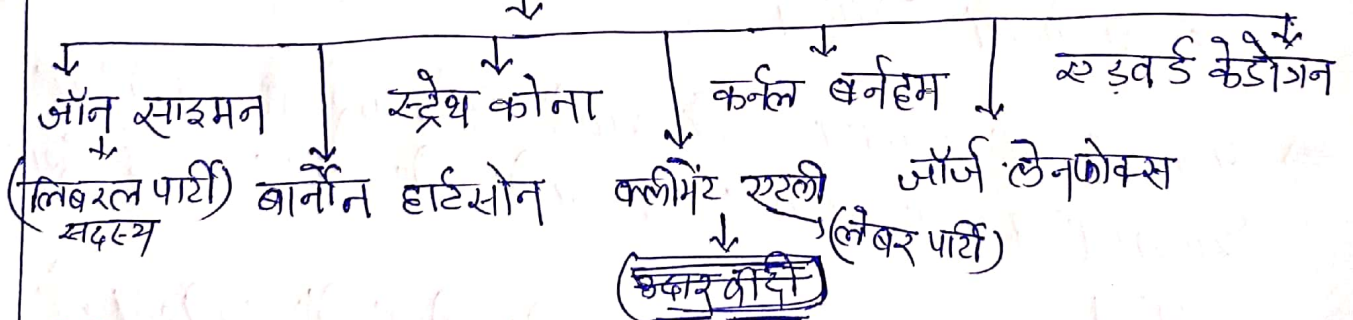
- ⇒ ~~1919 के एक्ट में उल्लेख था कि यह अचि~~
- ⇒ 1919 ई० के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि, अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि यह अधिनियम व्यवहारतः कहीं तक सफल रहा।

व्यक्ति :- ब्रिटेन प्रधान मंत्री :- बाल्डविन (कनजरवैटिव दल)
भारत सचिव → ~~बाल्डविन~~ वर्केनहेड
वायसराय → इरविन

ब्रिटेन सरकार ने दो वर्ष पहले ही इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का गठन किया।

→ Nov-1924

इस कमीशन का अध्यक्ष → सर जॉन साइमन थे।
इसमें कुल → 7 सदस्य थे (सभी अंग्रेज)



विरोध का कारण :-

- ① कमीशन की नियुक्ति दो वर्ष पूर्व होना
- ② भारतीयों को शामिल नहीं करना

सोचक तथ्य :- इरविन ने दो भारतीयों का नाम भेजा था लेकिन बाद में वापस ले लिया :-

- (1) मो० अली जिन्ना
- (2) जे० बहादुर खान

= विरोध

1927 ई० में मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय ~~किया~~ लिया गया।

- अव्यवस्था → M. A. Ansari
- ⇒ जिन्ना ने भी बहिष्कार किया।
 - ⇒ हिन्दू महासभा ने भी बहिष्कार का समर्थन किया

समर्थन :- मद्रास की अस्टिस पार्टी,
पंजाब की यूनिवर्सिस्ट पार्टी,
अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन
मो० ~~बिन्ना~~ वाला सफी वाले मुस्लिम लीग का खुलकर

- ⇒ आयोग 3 Feb 1928 को बम्बई पहुँचा तो इसका भयंकर जगह-जगह विरोध हुआ। अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ।

- ⇒ साइमन का स्वागत काले झण्डे दिखाकर किया गया 'साइमन वापस जाओ' के नारे से पूरा बम्बई उँज उठा।

Note :- 1928-29 के बीच में कमीशन ने भारत में दो बार यात्रा किया।

और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर लन्दन में आयोजित होने वाले काले गोलमेज सम्मेलन में विचार होने वाला था।

टिप्पणी → सर गिर्वर्यामी अंगर ने इसे रकदी की टेक्री में फेंकने लावक बताया ।

जन-प्रतिक्रिया :

- बम्बई पहुँचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालें एवं जुलूसों का आयोजन किया गया ।
- केंद्रीय विधानसभा भी साइमन का स्वागत करने से इंकार कर दिया ।

Note:- साइमन जो बैंक का नारा इस्मफ मेहर अली ने दिया ।

- लखनऊ में साइमन का अखिपेशन हो रहा था वहाँ पर खली कुज्जां ने पंतग और ठुबारे पर simon go back लिखकर उड़ा दिया जो एक भाखिपेशन में गिर गया ।

- लाहौर में लाला जी के नेतृत्व में साइमन का विरोध किया जा रहा था । उसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लाला जी के सर पर चोट लगाने से लाला जी का मृत्यु हो गई ।

उसी दौरान लाला जी ने बोले →

“मैंने ऊपर जो लाठियों का पहार किया गया है यही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी किल साबित होगी ।”

पुलिस अधिकारी → सांडर्स

जे. के. नहड़ ने भारतीयों को कहा की आप गलत विरोध कर रहे हैं , आप सभी मिलकर एक संविधान बनाइए जो हम आपको डोमैनिथन स्टेट्स दे देंगे ।

उसी के कहने पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था।

⇒ साइमन कमीशन का प्रतिवेदन

- ① द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना
- ② भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए
- ③ केन्द्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाय।
- ④ उच्च न्यायलय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाय।
- ⑤ वर्मा को भारत से विलग किया जाय उड़ीसा को एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाय
- ⑥ प्रांतीय विधानमण्डलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाय।
- ⑦ मताधिकार का विस्तार करने 2.8% से बढ़ाकर 10% - 15% तक बढ़ाने की बात
- ⑧ गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें इत्यादि।